



मुख्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यावसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4543/मुख्या. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17/12/2015

श्री विश्वजीत मित्रा
(अध्यक्ष),
छत्तीसगढ़ नगरिक संघर्ष समिति,
एफ-8, पिक सिटी, न्यू गायत्री नगर
रायपुर (छ.ग.)

- विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।
- संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 001 दिनांक 26/11/2015 एवं इस कार्यालय में आवक दिनांक 28/11/2015.

-----:OO:-----

उपरोक्त विषयान्तगत सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि वर्ष 2014 तथा चालू वर्ष 2015 में वर्तमान तक रायपुर शहर में शादी हाल, मैरिज गार्डन इत्यादि, बरात के साथ चलने वाले तथा गणेश एवं दुर्गा विसर्जन हेतु झांकी के साथ चलने वाले डी.जे. के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का ध्वनि मापन नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

JK


17/12/15

जनसूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू एच.आई.जी. 9,10,11- टाटीबंध, रायपुर

क्रमांक 2613/क्षेका/छ.प.सं.मं./2015 रायपुर दिनांक 10/12/2015

प्रति,

जन सूचना अधिकारी,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल,
मंडल मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 4168 दिनांक 28.11.2015.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार वांछित जानकारी निरंक है।


जनसूचना अधिकारी

0/c

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
hu



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,

कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) – 492099

क्रमांक 4289/ज.सू./छ.ग.प.सं.मं./2015

रायपुर, दिनांक 4/12/2015

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

✓ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :- भारत शासन की वेब साईट पोर्टल CPGRAMS पर ONLINE प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 6-09/2015/32 दिनांक 24/11/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत शासन की वेब साईट पोर्टल CPGRAMS पर ONLINE प्राप्त शिकायत क्रमांक DARPGC/E/2015/13474 आवेदक श्री जयगोपाल सोनी, जाजंगीर चांपा (छ.ग.) द्वारा शिकायत में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन के पब्लिक अथोरिटी द्वारा आर.टी.आई. के तहत प्राप्त आवेदनो के प्रतिउत्तर वेब साईट मे अपलोड नही कराया जा रहा है। जबकि इस संबंध में Government of india Ministry of personnel, public Grievances & pensions Department of personnel & Training का समय समय पर सर्कुलर जारी किया गया 15 अप्रैल 2013, 22 सितंबर 2014, 21 अक्टूबर 2014 तथा 29 जून 2015 सर्कुलर की छांयाप्रति संलग्न है। सर्कुलर में Implementation of suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 – issue of guidelines regarding सर्कुलर मे निर्देशानुसार आर. टी.आई. के तहत प्राप्त आवेदनो के प्रतिउत्तर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के वेब साईट मे बोर्ड मुख्यालय मे पदस्थ प्रोग्रामर की सहायता से अपलोड कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर एक्शन टेकन रिपोर्ट/ पालनार्थ रिपोर्ट सात दिवस के भीतर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करे। जिससे भारत शासन की वेब साईट पोर्टल CPGRAMS पर ONLINE प्राप्त शिकायत का निराकरण किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

रायपुर (छ.ग.)

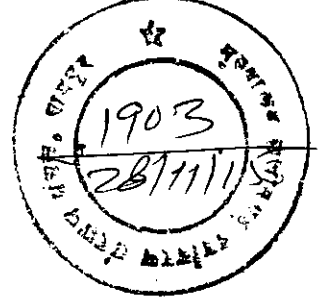
क्रमांक / ज.सू. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक / / 2015

1. श्री ए.सी. मालू, अधीक्षण अभियंता, श्री आर.आर. सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री मनीष कश्यप, कार्यपालन अभियंता, श्री ए.के. त्रिवेदी, मुख्य रसायनज्ञ, श्री ए.पी. सावंत, जनसंपर्क अधिकारी, श्री एस.एम. त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री राहुल सोनी, सहायक प्रोग्रामर (एन.आई.सी) की ओर सूचनार्थ आर.टी.आई. के तहत प्राप्त आवेदनो के प्रतिउत्तर एवं अपील आदेश छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के वेब साईट मे अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in



क्रमांक एफ 6-09/2015/32
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 24/11/2015.

1. सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
कक्ष-1, मंत्रालय नया रायपुर
(छ.ग.)
2. सचिव,
राजस्व विभाग
मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)
3. प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)
4. प्रमुख सचिव,
सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
5. सदस्य सचिव,
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- भारत शासन की वेबसाइट पोर्टल CPGRAMS पर ONLINE प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु।

—00—

विषयांतर्गत भारत शासन की वेब साइट पोर्टल CPGRAMS पर प्राप्त आनलाईन शिकायत क्रमांक DARPGC/E/2015/13474 आवेदक श्री जयगोपाल सोनी, जाजंगीर चांपा (छ0ग0) की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ आदेशानुसार कृपया उक्त आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से आवेदक को एवं इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(रिजीना टोप्पो)
संयुक्त सचिव

पं.
20/10/15

20/10

Grievance Details



Registration Number : DARPG/E/2015/13474
Registration Date : 08 Oct 2015
Complainant's Name : Jaigopal Soni
Grievance Category : State Government Related - Others
Letter No & Date : ,10/8/2015 12:00:00 AM
Client Status : General Public
Address : Sonar Para,
Champa
-495671
State/UT : Chhattisgarh
District : Janjgir - Champa
Contact No. : ,8987582449
E-mail ID : jaigopalsoni@gmail.com
Attachment : Open

Grievance Description :

None of the Public Authority in Government of Chhattisgarh has uploaded copies of application and appeal received along with its replies with search facility in its website in compliance to the DoPT OM Dated 15 April 2013, Dated 22 Sep 2014, Dated 21 Oct 2014 and DoPT OM Dated 29 June 2015. I tried to search websites of State Public Authorities like General Administration Department, Revenue Department, Energy Department, State Information Commission, Different District Collectors, Commissioners and Revenues Courts of Government of Chhattisgarh but links to requests and appeals filled by me but I did not find the same. Kindly direct the Public Authorities of Chhattisgarh Government to honor the Office Memorandum of DoPT and upload the copy of request, appeals and decisions in thier website which is not done so far in compliance to earlier circulars of DoPT and provide the url link. Information asked by me were useful for general public and it must be proactively disclosed in Public Authority General Administration Department GoCG website as per compliance of act and instructions issued by CIC DoPT. Copy of Circulars are attached for your reference and necessary action.

16/10/15

17/10

No.1/6/2011-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 15th April, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of *suo motu* disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 – Issue of guidelines regarding:

Section 4(1)(b) of the RTI Act lays down the information which should be disclosed by Public Authorities on a *suo motu* or proactive basis. Section 4(2) and Section 4(3) prescribe the method of dissemination of this information. The purpose of *suo motu* disclosures under Section 4 is to place large amount of information in public domain on a proactive basis to make the functioning of the Public Authorities more transparent and also to reduce the need for filing individual RTI applications.

2. Since the promulgation of the Act in 2005, large amount of information relating to functioning of the government is being put in public domain. However, the quality and quantity of proactive disclosure is not up to the desired level. It was felt that the weak implementation of the Section 4 of the RTI Act is partly due to the fact that certain provisions of this Section have not been fully detailed and, in case of certain other provisions there is need for laying down detailed guidelines. Further there is need to set up a compliance mechanism to ensure that requirements under section 4 of the RTI Act are met.

3. In order to address the above, Government of India constituted a Task Force on *suo motu* disclosure under the RTI Act, 2005 in May 2011 which included representatives of civil society organizations active in the field of Right to Information, for strengthening compliance with provisions for *suo motu* or proactive disclosure as given in Section 4 of the RTI Act, 2005. Based on the report of the Task Force, the Government have decided to issue guidelines for *suo motu* disclosure under section 4 of the RTI Act.

4. Guidelines for Central Government Ministries/Departments are on:
- Suo motu disclosure of more items under Section 4.
 - Guidelines for digital publication of proactive disclosure under Section 4.
 - Detailing of Section 4(1)(b)(iii), 4(1)(b)(iv), 4(1)(b)(xi) and 4(1)(b)(xiv)
 - Compliance mechanism for suo motu disclosure (proactive disclosure) under the RTI Act, 2005.
5. The above guidelines are enclosed. However, it may be kept in mind that proactive disclosure should be done in the local language so that it remains accessible to public. It should be presented in a form that is easily understood and if technical words are used they should be carefully explained. As provided in section 4, disclosure should be made in as many mediums as feasible and disclosures should be kept up to date. The disclosure of information may be made keeping in mind the provisions of Section 8 to 11 of the RTI Act.
6. Central Government Ministries/ Departments should undertake suo motu disclosure and ensure compliance based on these guidelines.
7. The enclosed guidelines may be brought to the notice of all for compliance.

Manoj Joshi
(Manoj Joshi)
Joint Secretary
Tele : 23093668

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Central Vigilance Commission, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Election Commission.
3. Central Information Commission.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

✓ Copy to : Chief Secretaries of all the States/UTs.

No.1/1/2013-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi-1
Dated: 21.10.2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Uploading of RTI replies on the respective website of Ministry/Department.

Attention is invited to DOPT's guidelines on suo motu disclosure issued vide O.M. No.1/6/2011-IR dated 15.4.2013 whereby Public Authorities have an obligation to proactively disclose RTI applications and appeals received by them and their responses on their websites.

2. In order to facilitate uploading of RTI applications/appeals received and their responses on the website, a new feature has been added to the CPIO/FAA's module on the "RTI online" portal on pilot basis for DOPT. This feature provides an option to the CPIO and FAA to upload the reply to RTI application and first appeal respectively on the website of the Department.

3. This feature is now being extended to other Ministries/Departments of Government of India. For displaying the RTI applications received in the Ministry/Department and the reply furnished thereof, by the use of the said feature, web services would be provided through a URL to each Ministry/Department by NIC/DOPT. The concerned Ministry/Department needs to consume this web service (by writing a program) to display the desired contents on its respective website. Accordingly, it is requested that the Ministries/Departments may contact NIC/DOPT (Shri Y. V. Ramana and Shri Manu Garg, Scientist 'D'/NIC. - Ph- 23040281) for this purpose. An immediate action is requested so that the facility to upload the reply to RTI application and first appeal respectively on the website of the respective Ministry/Department may be started w.e.f. 31st October, 2014.

4. It may be noted that RTI applications and appeals received and their responses relating to the personal information of an individual may not be disclosed, if they do not serve any public interest.

Sandeep Jain
(Sandeep Jain)
Director(IR)
23092755

To

All Ministries/Departments of Government of India

No.1/34/2013-IR

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-1

Dated: 29th June 2015

Office Memorandum

Subject: Implementation of Suo Motu Disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005

Attention is invited to detailed guidelines on implementation of suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 issued vide this department's O.M. No.1/6/2011-IR dated 15.4.2013. Subsequently, a Committee of experts consisting of Shri A.N.Tiwari, Chief Information Commissioner(Retd) and Dr. M.M.Ansari, Information Commissioner(Retd) (of Central Information Commission) was constituted to recommend, interalia, measures to further strengthen implementation of Section 4 of the RTI Act, 2005. The Committee has, interalia, made the following recommendations which have been duly accepted by the competent authority:-

- 1) All the details of the public authority may be uploaded on its website. Access to information should be made user-friendly for which appropriate information technology infrastructure should be suitably designed, developed and operationalised.
- 2) All the training modules for professional upgradation of employees should incorporate matter relating to the virtues of transparency and open government and RTI law.
- 3) In order to minimise the burden of servicing RTI applications, the public authorities with high public dealings should put in place an effective system to redress the grievances of affected persons. At the sub-organisational levels, there should be cooperation and coordination between the Central Public Information Officers and the officers responsible for addressing public grievances.
- 4) In order to reduce the number of RTI applications relating to service matters, the information relating to recruitment, promotion and transfers should be brought into public domain promptly.
- 5) The retention and maintenance of specific documents for specified duration should be clearly spelt by each public authority in respect of its documents.

No 1/6/2011-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Personnel Training

North Block, New Delhi-110001
Dated 22nd September, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Guidelines on implementation of suo-motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 — Compliance of.

Attention is invited to this Department's O.M. of even no. dated 15.4.2013 and subsequent reminder dated 10.12.2013 on the subject mentioned above.

2. In that O.M., it was mentioned that each Ministry/Public Authority shall ensure that the guidelines for suo motu disclosure under RTI are fully operationalised within a period of 6 months from the date of their issuance i.e. 15.04.2013. It was also mentioned that the Action Taken Report on the compliance of guidelines should be sent, alongwith the URL link, to the DoPT and the Central Information Commission soon after the expiry of the initial period of the 6 months. It has been noticed that most of the Ministries/Departments/Public Authorities have not sent the compliance report/Action Taken Report to this Department and Central Information Commission.

3. It was required that each Ministry/Public Authority should get its proactive disclosure package audited by third party every year and such audit should be communicated to the CIC through publication on their own website. It has been noticed that most of the Ministries/Public Authorities have not yet got their proactive disclosure package audited by a third party.

4. It is once again requested that the guidelines mentioned in O.M. dated 15.4.2013 be complied with and the proactive disclosure package be got audited by a third party. The compliance report may be sent to this Department and the Central Information Commission, at the earliest.


(Mamta Kundra)
Joint Secretary
Tel. 2309 4276

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission /Lok Sabha Sect/ Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs -